नईदुनिया

जिनपिंग के अमेरिका पहुंचते ही ट्रंप से होगा आमना सामना, 25 सितंबर को होगी उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक

बीजिंग

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह अमेरिका के तीन दिवसीय महत्वपूर्ण राजकीय दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उच्च स्तरीय बातचीत करेंगे। बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि शी जिनपिंग तेईस से पच्चीस सितंबर तक अमेरिका में रहेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन के अनुसार, इस आगामी बैठक के दौरान दोनों शीर्ष नेताओं के बीच चीन-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ वैश्विक शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास से जुड़े तमाम प्रमुख मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। चीन का यह भी कहना है कि वह अमेरिका के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच रचनात्मक रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने, आपसी संवाद को बढ़ाने और वर्तमान मतभेदों को उचित तरीके से प्रबंधित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दुनिया की इन दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच हो रही इस मुलाकात को व्यापार, अत्याधुनिक तकनीक और भू-राजनीतिक तनावों को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

कूटनीतिक प्रोटोकाल से हटकर एक विशेष पहल के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड खुद ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पहुंचने पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करेंगे, जबकि दोनों नेताओं के बीच मुख्य और निर्णायक बैठक होने की उम्मीद है। पिछले साल मई में ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान बीजिंग पहुंचने पर चीनी उपराष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया था, जिसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति का यह व्यक्तिगत स्वागत दोनों देशों के रिश्तों में कूटनीतिक गर्माहट लाने का संकेत देता है। हाल ही में एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया था कि वे इस मुलाकात के दौरान व्यापार और तकनीकी प्रतिस्पर्धा से लेकर लगभग हर संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर चर्चा करेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि पिछले लगभग एक साल से दोनों देशों के बीच टैरिफ और व्यापारिक मोर्चे पर केवल एक अस्थायी समझ ही बन पाई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस या स्थायी व्यापार समझौता नहीं हो सका है, जिसे इस बैठक में अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ताइवान की संप्रभुता, दक्षिण चीन सागर में सैन्य गतिविधियों और उच्च तकनीक आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच लंबे समय से चला आ रहा रणनीतिक तनाव भी इस उच्च स्तरीय वार्ता के सबसे प्रमुख और संवेदनशील एजेंडे में शामिल रहने वाला है।

न्यूज ब्रीफ

ईरान ने रद की तेहरान से बगदाद और मस्कट जाने वाली उड़ानें, टर्किश एयरलाइंस की सेवा मार्च तक बंद

तेहरान। ईरान ने तेहरान से बगदाद और मस्कट जाने वाली उड़ानें रद कर दी हैं। ऐसा क्षेत्रीय एयरपोर्ट्स पर अमेरिकी दबाव बढ़ने के कारण किया गया है। इस दबाव का मकसद ईरान की एयरलाइंस को इंटरनेशनल आपरेशन्स से अलग-थलग करना है। ईरान के सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन ने कहा कि इराकी और ओमान की राजधानियों के लिए उड़ानें 23 सितंबर को स्थानीय समयानुसार रात 12 बजे से रद कर दी जाएंगी। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने यह जानकारी दी। एजेंसी ने बताया कि ईरानी अधिकारी बगदाद जाने वाली उड़ानों को नजफ की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तस्नीम ने कहा कि बाकी इंटरनेशनल उड़ानें, जिनमें इस्तांबुल के लिए सेवाएं भी शामिल हैं, तय समय के अनुसार चलेंगी। इराक सिविल एविएशन अथारिटी के सूत्रों ने बताया कि इराकी सरकार ने अधिकारियों को बगदड्डाद के लिए ईरानी उड़ानें रोकने का आदेश दिया था। ईरान के सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन के प्रवक्ता माजिद अखवन ने भी कहा कि मस्कट एयरपोर्ट अब ईरानी यात्रियों को स्वीकार नहीं करेगा और तेहरान इन प्रतिबंधों को लेकर ओमान के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। इन उड़ानों का रद होना ईरान के एविएशन सेक्टर के खिलाफ वाशिंगटन के तेज किए गए अभियान का शुरुआती नतीजा है। अमेरिकी वित्त सचिव स्काट बेसेंट ने कहा कि ईरानी एयरलाइंस 23 सितंबर से इंटरनेशनल आपरेशन्स से प्रभावी रूप से बाहर हो जाएंगी। उन्होंने एयरपोर्ट्स, फ्यूल सप्लायर्स, ग्राउंड-हैंडलिंग फर्मों और अन्य कंपनियों को चेतावनी दी कि प्रतिबंधों का सामना कर रही ईरानी एयरलाइंस को सेवाएं देने से उन पर अमेरिकी जुर्माना लग सकता है।

नेपाल को पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका देगा 31 मिलियन डालर की अतिरिक्त सहायता

काठमांडू। अमेरिका ने नेपाल में बाढ़ के बाद पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त 31 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता देने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की राजनीतिक मामलों की उपसचिव एलिसन हुकर ने न्यूयार्क में नेपाल के विदेशमंत्री शिशिर खनाल के साथ मुलाकात के दौरान यह घोषणा की। बैठक में हुकर ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों और अब भी लापता करीब 70 अमेरिकी नागरिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिका ने प्रभावित क्षेत्रों में परिवहन बुनियादी ढांचे की बहाली और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत करने के लिए 10 मिलियन डालर मूल्य के स्थायी तथा जरूरत के अनुसार स्थापित किए जा सकने वाले पुल उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इन पुलों की खरीद अमेरिकी कंपनियों से की जाएगी। इसी तरह, प्रभावित समुदायों के लिए पेयजल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई, आश्रय, संरक्षण, आजीविका और सर्दियों के लिए आवश्यक सहायता समेत विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त 8 मिलियन डालर उपलब्ध कराने की योजना है। बाढ़ के बाद आपदा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए अमेरिका में निर्मित ड्रोन उपलब्ध कराने पर 13 मिलियन डालर खर्च करने की योजना भी घोषित की गई है। इस घोषणा के साथ नेपाल में बाढ़ राहत और पुनर्स्थापना प्रयासों के लिए अमेरिका की कुल सहायता 36 मिलियन डालर से अधिक हो गई है। अमेरिकी दूतावास ने यह जानकारी दी।

ईरान के रणनीतिक केशम द्वीप के पास जोरदार धमाके

तेहरान। ईरान के रणनीतिक केशम द्वीप के पास जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। यह आवाज

समुद्र की तरफ से आई। फिलहाल द्वीप के भू-भाग पर किसी मिसाइल या राकेट के गिरने की पुष्टि नहीं हुई है। यह रणनीतिक इलाका होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित है। अनादोलू की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के सरकारी मीडिया और इरना न्यूज एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। इरना ने साफ किया है कि यह आवाज जमीन की तरफ से नहीं, बल्कि समुद्र की तरफ से आई थी। एजेंसी ने कहा कि द्वीप पर कोई राकेट या मिसाइल नहीं गिरी। स्थानीय अधिकारियों ने धमाके की असल वजह पर अब तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थित केशम द्वीप खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। यह घटना होर्मुज में लगातार चल रहे समुद्री और सैन्य तनाव के बीच हुई है। यह ऊर्जा के परिवहन का एक अहम रास्ता है और ईरान से जुड़े संघर्षों का मुख्य केंद्र रहा है। इससे पहले 16 सितंबर को भी केशम द्वीप के तटवर्ती इलाके में धमाके हो चुके हैं।

जम्मू से कश्मीर तक सफर का नया इतिहास

9.28 किमी लंबी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल

डॉ. शिशिर उपाध्याय, जम्मू से

जम्मू। कभी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर घंटों जाम में फंसे रहने की कहानियां आम थीं, लेकिन आज वही सफर देश की सबसे आधुनिक और सुरक्षित टनल से मिनटों में पूरा हो रहा है। नाम है डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे पहले चेनानी-नाशरी टनल के नाम से जाना जाता था। यह टनल न सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि जम्मू-कश्मीर की लाइफलाइन भी बन चुकी है। यह टनल नेशनल हाईवे-44 पर उधमपुर के चेनानी को रामबन के नाशरी से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 9.28 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी टू-लेन सड़क टनल और एशिया की सबसे लंबी बाय-डायरेक्शनल हाईवे टनल बनाती है। समुद्र तल से 4,000 फीट की ऊंचाई पर निचली हिमालय पर्वत श्रृंखला को चीरकर बनाई गई इस टनल का निर्माण 3,720 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इसका उद्घाटन किया था और 2019 में इसका नाम जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। मुख्य टनल 13 मीटर चौड़ी है, जिसमें दो लेन हैं। इसके समानांतर 6 मीटर चौड़ी एक अलग एस्केप टनल यानी राहत टनल बनाई गई है। दोनों टनल को हर 300 मीटर पर 29 क्रॉस पैसेज यानी गेट्स से जोड़ा गया है। यही गेट्स किसी भी आपात स्थिति में जीवनरक्षक बनते हैं।

टनल बनने के फायदे

दूरी और समय की बचत : इस टनल के बनने से जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी 31 से 40 किलोमीटर कम हो गई है। पहले पटनीटॉप के घुमावदार और खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता था, जिसमें 2 से 2.5 घंटे लगते थे। अब वही दूरी 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाती है। कुल यात्रा में 2 घंटे की बचत होती है।

ईंधन की बचत : इस टनल से रोजाना लगभग 27 लाख रुपये के ईंधन की बचत होती है। पहाड़ों की चढ़ाई नहीं होने से गाड़ियों का माइलेज बेहतर हुआ है।

हर मौसम में कनेक्टिविटी : पहले बर्फबारी और भूस्खलन से हाईवे 40 से 50 दिन बंद रहता था। अब टनल के कारण जम्मू-कश्मीर साल भर जुड़ा रहता है। सेना के मूवमेंट, मेडिकल इमरजेंसी और सेब-फल ट्रांसपोर्ट के लिए यह वरदान साबित हुई है।

पर्यावरण और वाहन की सुरक्षा : पहाड़ी रास्ते की तीखी ढलानों से बचने से टायर-घिसाई और एक्सीडेंट में भारी कमी आई है। डोडा, किश्तवाड़, रामबन जैसे जिलों का जम्मू से संपर्क आसान हुआ है। पर्यटन और व्यापार दोनों बढ़े हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक भरोसे का नाम है, जो कहती है, चाहे मौसम कैसा भी हो, जम्मू से कश्मीर का रिश्ता अब कभी नहीं टूटेगा।

सुरक्षा ऐसी कि 10 मिनट में पहुंचेगी मदद

इस टनल को सुरक्षा के हर मापदंड पर परखा गया है। टनल के अंदर 128 हाई-रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे नजर रखते हैं। कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाती है। टनल में हर एक किलोमीटर पर हेल्प डेस्क बनाई गई है। इमरजेंसी में जैसे ही कोई यात्री हेल्प डेस्क का दरवाजा खोलता है, सुरक्षा टीम से तत्काल कनेक्ट हो जाता है। दावा है कि आगजनी, एक्सीडेंट या किसी भी आपात स्थिति में 10 मिनट के अंदर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच जाती है और 29 गेट्स के जरिए एस्केप टनल से राहत पहुंचाई जाती है। देश की यह पहली टनल है, जहां ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है। टनल के अंदर फ्रेश एयर के लिए और धुएं व पॉल्यूटेड हवा को बाहर निकालने के लिए बड़े-बड़े फैन लगाए गए हैं। हर 8 मीटर पर ताजी हवा के लिए इनलेट और हर 100 मीटर पर आउटलेट बनाए गए हैं। यह दुनिया की छठी ऐसी टनल है, जिसमें इस तरह की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। एनएचएआई के आंकड़ों के अनुसार, इस टनल से प्रतिदिन औसतन 5,500 से 7,000 वाहन गुजरते हैं। पर्यटन सीजन, अमरनाथ यात्रा और सेब सीजन में यह आंकड़ा 10 हजार से भी ऊपर पहुंच जाता है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले लगभग 70 प्रतिशत छोटे-बड़े वाहन अब इसी टनल का उपयोग करते हैं।

संरा महासभा में तुर्किये के दृष्टिकोण का विरोध, इजराइल का बहिर्गमन

न्यूयार्क

तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में एक कड़े भाषण में गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल की कार्रवाई की निंदा की। इससे नाराज इजराइली प्रतिनिधिमंडल बहिर्गमन (वाकआउट) कर गया। मगर फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों ने तालियां बजाईं। एर्दोगन ने गाजा में इजराइल के लगातार हो रहे युद्ध अपराधों और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तियों में रहने वाले लोगों द्वारा किए जा रहे हमलों और हिंसा के बढ़ने का मुद्दा उठाया।

रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन से हमने युद्धविराम में योगदान दिया। लेकिन इस तथाकथित युद्धविराम के बावजूद गाजा में 1,300 से ज्यादा आम नागरिकों की हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि हमास और अन्य फिलिस्तीनी समूहों ने अक्टूबर के युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इजराइल गाजा में अपनी कार्रवाई बंद नहीं कर रहा है। एर्दोगन ने कहा, हम एक ऐसी नरसंहार वाली मानसिकता का सामना कर रहे हैं जिसका खून-खराबे से कभी मन नहीं भरता। इंसानियत, दया या जमीर रखने वाला कोई भी व्यक्ति इससे आंखें नहीं मूंद सकता। एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वह संघर्ष वाले इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा, इक्यासी (81) साल पहले, दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि यूएन अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहा है।

एर्दोगन ने कहा कि यूएन बेअसर हो गया है और फिलिस्तीन, लेबनान और सूडान में उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। एर्दोगन ने दुनिया के नेताओं की यूएन बैठक में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की गैर मौजूदगी का भी जिक्र किया, क्योंकि अमेरिका ने फिलिस्तीनी नेता को देश में आने के लिए वीजा देने से मना कर दिया था। ऐसा दो साल में दूसरी बार हुआ है।

एर्दोगन ने कहा, भले ही राष्ट्रपति अब्बास यहां हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम फिलिस्तीन को आजाद और संप्रभु देश मानते हैं और उसकी आवाज उठाते रहेंगे। तुर्किये के राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर रूस के युद्ध का भी जिक्र किया और कहा कि अब इस संघर्ष को खत्म करने का समय आ गया है।

न्यूयार्क में नेपाल के विदेशमंत्री खनाल ने एस. जयशंकर से की मुलाकात

काठमांडू। नेपाल के विदेशमंत्री शिशिर खनाल ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की 81वीं महासभा के अवसर पर अमेरिका के न्यूयार्क में भारत के विदेशमंत्री डा. एस. जयशंकर से मुलाकात की। नेपाल के विदेश मंत्री खनाल ने मुलाकात के दौरान नेपाल में हाल ही में आई विनाशकारी भोटेकोशी बाढ़ के बाद भारत सरकार और भारतीय जनता की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता तथा तत्काल उपलब्ध कराई गई महत्वपूर्ण सहायता के लिए धन्यवाद दिया। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में दोनों मंत्रियों ने नेपाल-भारत संबंधों के विभिन्न पहलुओं और आपसी हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दोनों के बीच नेपाल और भारत के बीच लंबे समय से कायम घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने तथा द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के विषय पर भी चर्चा हुई ।

उत्तर कोरिया के हाथ लगा रूस का गेरान ड्रोन, सैमसंग से टोयोटा तक की फैक्ट्रियां बन सकती हैं निशाना

मास्को

रूस में बन रहे उन्नत गेरान श्रेणी के ड्रोन और उनकी मारक तकनीक को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इसका असर अब केवल यूक्रेन युद्ध तक सीमित नहीं रहने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि रूस ने इन घातक ड्रोन्स या उनकी निर्माण तकनीक को उत्तर कोरिया तक पहुंचा दिया, तो इससे कोरियाई प्रायद्वीप और एशिया के सामरिक संतुलन पर कितना गहरा और खतरनाक असर पड़ेगा। रूस के तातारस्तान स्थित अलाबुगा विशेष आर्थिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गेरान ड्रोन का उत्पादन किया जाता है, और रिपोर्ट्स के अनुसार वहां संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बचने के लिए छात्र वीजा की आड़ में हजारों उत्तर कोरियाई नागरिकों को कामगारों के रूप में भेजा गया है। बहुपक्षीय प्रतिबंध निगरानी समूहों की रिपोर्टों का अनुमान है कि रूस में ड्रोन निर्माण से जुड़ी गतिविधियों में लगभग पच्चीस हजार तक उत्तर कोरियाई नागरिक शामिल हो सकते हैं, जिन्हें इस पूरी अत्याधुनिक तकनीकी प्रक्रिया की गहरी जानकारी मिल रही है।

रूसी सैन्य और रक्षा क्षेत्रों में काम कर रहे इन उत्तर कोरियाई कामगारों के माध्यम से यदि गेरान ड्रोन की तकनीक प्योंगयांग के हाथों में पहुंचती है, तो यह दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों के लिए एक विकट चुनौती बन सकती है।

रूस द्वारा यूक्रेन में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले गेरान-2 और विशेष रूप से छह सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले तथा नब्बे किलोग्राम तक के विस्फोटक ले जाने में सक्षम गेरान-5 जैसे ड्रोन अपनी अत्यधिक गति और सटीक मारक क्षमता के कारण दुश्मन के रक्षा तंत्र को भेदने में माहिर माने जाते हैं। रूसी सैन्य विश्लेषकों और ब्लाग्स के हालिया आकलन के अनुसार, यदि उत्तर कोरिया को ऐसी लंबी दूरी की और तेज रफ्तार ड्रोन क्षमता हासिल हो जाती है, तो पारंपरिक सैन्य ठिकानों के अलावा उसके निशाने पर दक्षिण कोरिया और जापान के प्रमुख औद्योगिक और ऊर्जा प्रतिष्ठान भी आ सकते हैं। इस संभावित भू-राजनीतिक खतरे के चलते दक्षिण कोरिया के बड़े तकनीकी और विनिर्माण केंद्रों, विशेष रूप से सीमा के करीब स्थित सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियों के उत्पादन संयंत्रों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं।

न्यूयार्क पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति, समझौता न होने पर ट्रंप ने इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करने की धमकी दी

न्यूयार्क

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए न्यूयार्क पहुंच गए। वह युद्ध पर ईरान का पक्ष रखेंगे और तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक समाधान की कोशिश करेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे चुके हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वे इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म कर देंगे।

इरना और अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, पेजेश्कियान महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि वह इस दौरान संघर्ष, कथित अपराधों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर ईरान के अविश्वास जैसे मुद्दों पर तेहरान का पक्ष रखेंगे। न्यूयार्क रवाना होने से पहले पेजेश्कियान ने कहा हम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ईरान का पक्ष मजबूती से रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र में हम जो मुद्दे उठाएंगे, उनमें ईरानी जनता

की दयनीय स्थिति, हुए अपराध और पैदा हुए अविश्वास को उजागर करना शामिल है। हम कई बार बातचीत की मेज पर बैठे और समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन दुर्भाग्य से, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे वादे पूरे नहीं किए गए और समझौतों को पैरों तले रौंद दिया गया।

पेजेश्कियान का आगमन ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र महासभा संबोधन के ठीक बाद हुआ, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ समझौता करने या इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के बीच एक विकल्प पेश किया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर संघर्ष खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ तो वे इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा फैसला लेना है।

ट्रंप ने कहा कि ईरान इंतजार कर रहा है कि अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। उन्होंने कहा कि चुनाव का तेहरान के प्रति उनके नजरिए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, ईरान के मामले में मैं चुनाव को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता और न ही दूंगा। यह मेरे दिमाग में भी नहीं आता। मेरे लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, जब ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों के बारे में बोलना शुरू किया तो ईरानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने वाकआउट करदिया। इरना के अनुसार, रवानगी से पहले पेजेश्कियान को पहले उप राष्ट्रपति मोहम्मद रजा अरेफ, सुप्रीम लीडर के कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय मामलों के डिप्टी होज्जतोलइस्लाम वालमोस्लेमिन मोहसेन कोमी और ईरानी कैबिनेट के सदस्यों ने आधिकारिक तौर पर विदाई दी।

न्यूयार्क में प्रवास के दौरान, पेजेश्कियान वहां मौजूद राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। साथ ही अमेरिका में रहने वाले पढ़े-लिखे ईरानियों, अमेरिकी विशिष्ट लोगों और थिंक टैंक के साथ अलग-अलग बातचीत भी करेंगे। पेजेश्कियान का भाषण ऐसे समय में होगा जब संयुक्त राष्ट्र में वाशिंगटन और तेहरान के रुख में जबरदस्त मतभेद है।